www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 241 | जौनपुर मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून का रास्ता साफ, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने "जागृत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026" पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि यह बड़ा कदम है और उन्होंने वाहेगुरु का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें यह सेवा करने का अवसर मिला, इसके लिए वह कृतज्ञ हैं और समूची सिख संगत का धन्यवाद करते हैं। हालांकि, फिलहाल यह कानून केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों पर ही लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य धर्मों के लोगों से बातचीत कर जल्द ही उनके लिए भी इसी तरह का कानून लाया जाएगा। नए कानून के तहत बेअदबी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्स्वरूपश (पवित्र ग्रंथ) को जानबूझकर फाड़ना, जलाना या किसी भी तरह से खंडित करना, पवित्र ग्रंथ पर थूकना, उसे गंदे हाथों से छूना या किसी ऐसी जगह रखना जहां उनकी गरिमा भंग होती हो, गुरु साहिब के स्वरूप को सार्वजनिक रूप से फेंकना या गलियोंध्नालियों में लावारिस छोड़ देना, पवित्र स्वरूप को चोरी करना या उसे मर्यादा के विरुद्ध अपने पास रखना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में शराब, तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना है।

बंगाल में 100 प्रतिशत भाजपा की बनेगी सरकार : हिमंता बिस्वा सरमा

गौरबाजार, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाएगी। पश्चिम बर्धमान जिले के गौरबाजार में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने यह बात कही। आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने पार्टी की जीत की संभावनाओं पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि परिणाम 100 प्रतिशत निश्चित है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए इस बार दो चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, जो पिछले चुनावों के बहु–चरणीय मतदान से अलग है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों, जबकि दूसरे चरण में सात जिलों की बाकी 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिससे पूरे राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस साल का चुनाव राज्य की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 2001 के एक चरणीय चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर चुनाव कई चरणों में हुए हैं, जिनमें 2021 का आठ चरणों वाला चुनाव भी शामिल है। इस बार सिर्फ दो चरणों में मतदान कराने का फैसला बेहतर प्रशासनिक तैयारी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है।

देश की संसद में तृणमूल का महिला विरोधी चेहरा उजागर : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी के शासनकाल में युवा भर्ती, शिक्षकों की नियुक्ति और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही चक्रवातों से प्रभावित लोगों के लिए आवंटित राहत निधि का भी दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने लोगों को लूटने में पीएचडी कर ली है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं देख रहा हूं कि बंगाल का चुनाव भाजपा के लोग नहीं, भाजपा के उम्मीदवार और कार्यकर्ता नहीं३ ये चुनाव तो बंगाल की मेरी जनता लड़ रही है, बंगाल के मेरे भाई–बहन चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के किसान और मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बंगाल में जहां भी जा रहा हूं यही भाव देख रहा हूं, इसलिए आज टीएमसी के गुंडे डर से कांप रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कह रहा है कि इस बार हर अत्याचार का हिसाब होगा। इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, गली–गली में सिर्फ एक ही नारा है, घर घर में एक ही संकल्प है– पलटानो दरकार, चाई भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं

कि भाजपा सरकार सबका साथ–सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी। चुन–चुन कर हिसाब लिया जाएगा। आप यहां भाजपा का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के 9 हजार रुपए सीधे जमा किए जाएंगे। साथ ही बंगाल की मंडियों से टीएमसी के दलालों को भी भगाया जाएगा, ताकि किसानों को उपज के उचित दाम मिल सकें। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार नीली क्रांति का विस्तार करेगी। भाजपा सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। पिछले दशक में भाजपा शासित राज्यों में मछली उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में मछली उत्पादन दोगुना हो गया है, और ओडिशा में 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि, बंगाल में पिछले दशक में मछली उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण टीएमसी की खराब नीतियां हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की सगी है, घुसपैठियों की सगी है। बाकी इनको किसी से कोई लेना–देना नहीं है। बीते 2–3 दिनों में देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया है। देश की बहन और बेटियों को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी ने इस कानून को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में टीएमसी का महिला–विरोधी रुख खुलकर सामने आया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद में चर्चा हुई। हालांकि, टीएमसी ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन नहीं किया। टीएमसी का मानना घ्है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं राज्य विधानसभा में उनसे सवाल करेंगी। महिला विधायकों की संख्या जितनी अधिक होगी, टीएमसी द्वारा महिलाओं के खिलाफ की गई हिंसा के कृत्यों के उजागर होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी बहनों–बेटियों के आरक्षण को रोक रही है, जबकि संसद में कानून बना है, लेकिन वह अपने वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने लगी है। ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने में जुटी है।

बढ़ती गर्मी को लेकर सीएम योगी की प्रदेशवासियों से खास अपील, जारी की पाती

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है और सूरज की तपिश दिन–ब–दिन तेज होती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पाती लिखकर लोगों से सावधानी बरतने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा, ष्मौसम की तरह फसलों का भी चक्र होता है। रबी की फसलों की कटाई हो चुकी है। नई फसल की उपज एवं मौसमी फल आपका स्वाद बढ़ा रहे हैं। लेकिन मौसम का चक्र अगर थोड़ा भी परिवर्तित हो जाए, तो बाढ़, सूखा, अकाल से लेकर महामारी तक मनुष्यों के लिए अभिशाप बन जाती हैं। प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप हर मौसम की तरह ग्रीष्म ऋतु आई है। बढ़ता तापमान हमें इसके दुष्प्रभावों से बचने तथा अपनी तैयारियां पूरी करने का संदेश दे रहा है।ष उन्होंने कहा, ष्प्रदेश के हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है, इसलिए सरकार ने कड़कड़ाती ठंड की तरह प्रचंड गर्मी की मार से बचाने की भी तैयारी कर ली है। शासन के हर स्तर पर समन्वित और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।ष सीएम ने बताया, ष्बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। पीक डिमांड को ध्यान में रखते हुए लगभग 34,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए सभी थर्मल पावर प्लांट को उनकी पूरी क्षमता से संचालित करने की व्यवस्था की गई है। प्रदेशभर में पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने का कार्य तात्कालिक रूप से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा, ष्सड़कों पर पानी का छिड़काव, छायादार क्षेत्रों की व्यवस्था, श्रमिकों को थकावट, निर्जलीकरण एवं लू से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कड़ी में औद्योगिक एवं निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य जांच शिविर स्थापित किए जाएंगे। हीट स्ट्रोक से प्रभावितों को तत्काल उपचार मिले, इसके लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है।

अच्छी सड़कें और बेहतर रेलवे बनेंगी विकसित भारत का मजबूत आधार : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि रेलवे और सड़कें केवल परिवहन के साधन नहीं हैं, बल्कि आर्थिक राष्ट्रों की नींव हैं। बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति भवन में भारतीय रेलवे के प्रोबेशनरी अधिकारियों और केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) के सहायक कार्यपालक अभियंताओं से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने यह बात कही। इस अवसर पर भारतीय रेलवे के 2022 और 2023 बैच के अधिकारी तथा केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़कें) के 2021, 2022, 2023 और 2024 बैच के सहायक कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने युवा

अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे महत्वपूर्ण समय में सार्वजनिक सेवा में आए हैं, जब देश 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अधिकारियों के निर्णय और कार्य सीधे तौर पर करोड़ों नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि रेलवे और राजमार्ग केवल यातायात के साधन नहीं हैं, बल्कि वे आर्थिक विस्तार, सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय एकीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। जब कोई रेलगाड़ी दूरस्थ गांव तक पहुंचती है या कोई राजमार्ग किसी क्षेत्र को जोड़ता है, तो वह उस क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास के नए द्वार खोलता है। उन्होंने कहा, "मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करता है, व्यापार को बढ़ावा देता है, निवेश आकर्षित करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। इससे विभिन्न क्षेत्रों और लोगों को एक–दूसरे के निकट लाकर राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है।" राष्ट्रपति ने अधिकारियों को याद दिलाया कि सफलता को केवल आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। उनके काम की असली कसौटी यह है कि वह आम लोगों के जीवन को कितना बेहतर बना पाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने युवा अधिकारियों से ईमानदारी, जवाबदेही और उत्कृष्टता के उच्च मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय और कठिन निर्णयों में यही मूल्य उनका मार्गदर्शन करेंगे।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और श्रीलंकाई राष्ट्रपति की अहम वार्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दो दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं। वहां पारंपरिक कंडियन डांस परफॉर्मेंस के जरिए भारत के उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति दिसानायका के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। मुलाकात की तस्वीरें साझा कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई, "भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने

आज कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास, मजबूत सभ्यता और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित भारत–श्रीलंका के कई तरह के संबंधों को और गहरा करने पर अच्छी बातचीत की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आगे बताया, "उन्होंने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और श्रीलंका में तूफान दित्वाह से प्रभावित इलाकों के लिए 450 मिलियन पैकेज के तहत लागू किए जा रहे प्रोजेक्ट्स समेत कई पहलों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की। इसमें भारतीय मूल के तमिल समुदाय के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन की कोशिशें भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने मछुआरों के मुद्दों को मानवीय तरीके से सुलझाने पर चर्चा की, और दोनों तरफ के मछली पकड़ने वाले समुदायों की रोजी–रोटी का भी ध्यान रखा।" भारतीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19–20 अप्रैल के दो दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे हैं। यह भारत के किसी उपराष्ट्रपति का पहला आधिकारिक श्रीलंका दौरा है। इससे पहले श्रीलंका के लिए रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति के एक्स हैंडल पर जानकारी दी गई कि 'भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, दो दिन के आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के लिए रवाना हो गए हैं। यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय दौरा है। इस दौरे के दौरान, वे द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे ।

भाजपा के सामने अन्नाद्रमुक का सरेंडर, आरएसएस को भी घेरा : राहुल गांधी

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु की सियासत चुनावी उबाल पर है और सत्ता की जंग अब खुली टक्कर में बदल चुकी है। जैसे–जैसे मतदान की घड़ी करीब आ रही है, आरोपों और पलटवार की धार और तेज होती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी की रैली से भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। उन्होंने एआईएडीएमके पर सीधे भाजपा के सामने समर्पण (सरेंडर) करने का आरोप जड़कर सत्ता समीकरणों को चुनौती दी है, जिससे राज्य की राजनीति में नई हलचल मच गई है।पूरी बात को ऐसे समझिए कि कन्याकुमारी में रैली के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एआईएडीएमके के नेताओं ने भ्रष्टाचार के कारण भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एआईएडीएमके का इस्तेमाल कर रही है।दूसरी ओर अपने संबोधन में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा को पसंद नहीं करता और तमिलनाडु पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। उनके मुताबिक, तमिलनाडु की पहचान, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए इस विचारधारा को समझना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सीधे तौर पर तमिलनाडु में मजबूत नहीं हो पा रही है, इसलिए वह एआईएडीएमके के जरिए राज्य की राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया तृणमूल कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप

हुगली, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को हुगली जिले के तारकेश्वर स्थित विवेकानंद सेवा केंद्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित चुनावी जनसभा से भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। इस जनसभा में तारकेश्वर के उम्मीदवार रामेंदु सिंहराय, हरिपाल की उम्मीदवार करबी मान्ना और सिंगूर के उम्मीदवार बेचाराम मान्ना भी मौजूद रहे। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के तृणमूल उम्मीदवारों के समर्थन में यह संयुक्त सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया–धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भाजपा की ओर से भय दिखाया जा रहा है। महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि यह वास्तव में महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा विधेयक नहीं, बल्कि परिसीमन से संबंधित एक चाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की बढ़ती सक्रियता पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर रोज–रोज ईडी की छापेमारी क्यों हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाल की जनता किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी।

महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज, फडणवीस बोले यह काला दिन है

मुंबई, (एजेंसी)। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने हालिया संसदीय नतीजों को सुधारवादी राजनीति के लिए ष्काला दिनष बताया और 131वें संशोधन विधेयक को दो–तिहाई बहुमत न मिलने पर निराशा व्यक्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेसवार्ता कर कहा कि आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 17 अप्रैल को हमारे राष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसे हम भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ कह सकते हैं क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलनी थी। हमें उम्मीद थी कि सभी दल इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, यूबीटी

(शिवसेना), शरद पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी सहित कई दलों ने महिला विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए विधेयक को आवश्यक दो–तिहाई बहुमत प्राप्त करने से रोक दिया। ऐसा करके उन्होंने 70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात किया और इस विधेयक के माध्यम से श्गर्भाशय वधश किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ष्इस तरह विधेयक को रद्द करने के बाद उन्होंने जो जश्न मनाया, वह वास्तव में भारत के महान समाज सुधारकों के आदर्शों पर तांडव था।मुझे गहरा दुख है कि जिस वर्ष हम महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं, उसी वर्ष इन पार्टियों ने उनके सिद्धांतों को त्याग दिया है। ये सभी पार्टियां, जो केवल अपने भाषणों में फुले का नाम लेती हैं, अब पूरी तरह बेनकाब हो गई हैं।ष उन्होंने राज्यव्यापी व्यापक जनसंपर्क अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा, ष्हम इस विधेयक के समर्थन में महाराष्ट्र भर की एक करोड़ महिलाओं के हस्ताक्षर एकत्र करेंगे। इसके साथ ही, हम तालुका स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। भारतीय पार्टी ने इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें हम अपने सहयोगियों को आमंत्रित करेंगे। इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा उद्देश्य कांग्रेस, शरद पवार और यूबीटी (शिव सेना) के इस मुद्दे पर रुख को उजागर करना है।

संपादकीय

प्रगति का लंबा रास्ता

साल 1990 में भारत में औसतन हर एक लाख शिशु जन्म के दौरान 508 माताओं की मौत होती थी। ये संख्या 2023 में 116 तक आ गिरी। फिर भी भारत वैश्विक स्तर पर कम विकसित देशों की श्रेणी में ही आता है। मातृत्व मृत्यु दर की अवस्था (शिशु को जन्म देने के क्रम में माताओं की होने वाली मौतें) सामाजिक विकास का एक प्रमुख पैमाना है। बीते साढ़े तीन दशक में भारत ने इस कसौटी पर अच्छी प्रगति की है। लेकिन 2015 के बाद से प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। मशहूर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लांसेट ने एक ताजा अध्ययन रिपोर्ट में बताया है कि साल से 2000 से 2015 की अवधि सबसे तेज प्रगति की रही, जब अस्पतालध क्लीनिक में प्रसव, प्रसव–पूर्व देखभाल में सुधार, और आम तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के कारण मातृत्व मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई। लेकिन 2015 से 2023 की अवधि में ये रफ्तार सुस्त हो गई है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा है कि ये परिघटना उन व्यवस्थागत चुनौतियों की ओर इशारा करती है, जिनका हल ढूंढना कठिन बना हुआ है। प्रसव के दौरान अधिक खून बहना, हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें, और आम देखभाल में कमी गर्भवस्था या डिलिवरी के दौरान माताओं की मौत की बड़ी वजहें बनी हुई हैं। ये वो कारण हैं, जिन्हें दूर किया जा सकता है, मगर उसके लिए लक्ष्य केंद्रित सार्वजनिक पहल की जरूरत है। संभवतरू इसमें कमी के कारण ही 2023 में भारत में 24,700 महिलाओं की मौत मां बनने के क्रम में हो गई। 1990 में ये संख्या 1.19 लाख और 2015 में 36,900 थी। जाहिर है, प्रगति का क्रम बना हुआ है, मगर वार्षिक प्रगति की रफ्तार धीमी हुई है। 1990 में भारत में औसतन हर एक लाख शिशु जन्म के क्रम में 508 माताओं की मौत होती थी। ये संख्या 2023 में 116 तक आ गिरी। इसके बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दर के साथ भारत वैश्विक स्तर पर नाईजीरिया, इथोपिया और पाकिस्तान जैसे कम विकसित देशों की श्रेणी में आता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत प्रति एक लाख जन्म पर मातृत्व मृत्यु दर को 70 के नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी भारत को अभी भी प्रगति का लंबा रास्ता तय करना है। अतरू जरूरी है कि इसकी रफ्तार धीमी ना होने दी जाए।

राहुल ने मोदी का जादू खत्म किया

शकील

सोचिए भारत की एकता और अखंडता के लिए यह कितना जरूरी है कि दक्षिण के राज्यों में ऐसा कोई संदेश नहीं जाए कि उनकी सीटें कम करने की साजिश हो रही है। उन्हें उत्तर भारत के मुकाबले कमजोर करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष ने इस माहौल को खत्म कर दिया। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए यह विपक्ष का बड़ा योगदान है। राहुल ने बिल्कुल सही कहानी सुनाई थी। जादूगर का जादू खत्म हो गया और जादूगर भी खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब उसकी वह कला जगलरी खत्म हो गई।महिला की आड़ में लाया गया परिसीमन बिल तो गिरा ही प्रधानमंत्री मोदी का खेल भी खत्म हो गया। शनिवार रात साढ़े आठ बजे प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी, समर्थकों, मीडिया और खुद को बहलाने के लिए भाषण दिया। नाम तो इसे राष्ट्र के नाम संबोधन का दिया गया था। मगर राष्ट्र के नाम संबोधन बहुत बड़ी चीज होती है। पूरा देश उत्सुकतापूर्वक सुनता है। देश के लिए कोई प्रेरणा होता है। हर कोई राष्ट्र को संबोधित नहीं कर सकता। यह विशेषाधिकार केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही होता है।लेकिन मोदीजी ने शनिवार रात इसे शिकवा शिकायत, रोना सहानुभूति पाने की कोशिश का जरिया बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी का अब तक सबसे कमजोर भाषण। और यह हम नहीं कह रहे। उनके समर्थक कह रहे हैं। वे समर्थक जिनमें उत्साह भरने के लिए मोदी ने यह भाषण दिया था। कुछ तो इन्दिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि कैसे वे हार को जीत के अवसरों में बदल देती थीं। मगर यह भूल गए कि वे इन्दिरा गांधी थीं। झूठ के मंच पर नहीं खड़ी थीं। उनके सिद्धांत थे, मूल्य थे। प्रगतिशील थीं। पूरे देश को साथ लेकर चलती थीं। नफरत और विभाजन की राजनीति नहीं करती थीं।कर पाएंगे या नहीं देखना होगा! लेकिन अगर कर दिया तो अगला राष्ट्र के नाम संबोधन रोने गाने के लिए नहीं देश को गर्व कराने वाला होगा। जो देश चाहता है। संबोधन में पाकिस्तान का नाम तो लिया मगर यह नहीं कह सके कि मेरी विदेश नीति की असफलता की वजह से आज वह दुनिया में केन्द्रीय भूमिका में आ गया है। पाकिस्तान का नाम लिया था तो यह भी बताना था कि उसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। हमारे विश्व रंगमंच से हटने से उत्पन्न शून्य ने उसे मौका दे दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह सब कुछ नहीं बोला कांग्रेस कांग्रेस और बाकी टीएमसी, डीएमके, सपा को कोसते रहे। सोचिए राष्ट्र के नाम संबोधन में यह होता है? यह पार्टियां तो राष्ट्र का हिस्सा हैं। राष्ट्र के बाहर जिनसे चुनौती है उन पर हमला करना था। पाकिस्तान, चीन, राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं कि मैं आपका राजनीतिक कैरियर खतम कर सकता हूं उन पर हमला करना था। जनता खुश होती। मगर यहां तो उल्टे आपके समर्थक दुखी और निराश हो गए। क्या राहुल गांधी की बात सही साबित हो गई। इतनी जल्दी। पहले भी उनकी कई बातें सही साबित हुई हैं कि किसान बिल वापस लेना पड़ेंगे, जाति गणना करना पड़ेगी। और भी कई। मगर यहां तो इतना तत्काल फल (परिणाम) आ रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। राहुल की शुक्रवार को लोकसभा में कही दो बातें सही साबित हो गईं। एक उन्होंने कहा था कि अभी आधे घंटे में यहीं इनका दक्षिणी राज्यों के साथ साजिश करने का बिल गिराएंगे। और वाकई वह बिल गिरा दिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि जादूगर का जादू खतम हो गया और खुद जादूगर भी। शनिवार को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद यह भी दिख गया। केवल एक गोदी मीडिया है जो अभी भी प्रधानमंत्री में जादू देख रहा है। वह अभी भी बताने में लगा है कि राहुल कांग्रेस, टीएमसी ममता, डीएमके स्टालिन, सपा अखिलेश सब खत्म हो गए। प्रधानमंत्री के एक भाषण ने इन सबकी राजनीति खत्म कर दी। मगर गोदी मीडिया के अलावा किसी को नहीं लग रहा कि मोदी में अब बाजी पलटने की क्षमता है। जिसे महिला बिल कह रहे हैं उसकी असलियत सबकी समझ में

आ गई है कि उसका महिलाओं से कोई संबंध नहीं था। वह तो मनमाने ढंग से अपने लिए जीतने वाली सीटें बढ़ाने का परिसीमन बिल था। दक्षिण के राज्यों में सौतेला समझने की भावना फैलाने वाला बिल। सोचिए भारत की एकता और अखंडता के लिए यह कितना जरूरी है कि दक्षिण के राज्यों में ऐसा कोई संदेश नहीं जाए कि उनकी सीटें कम करने की साजिश हो रही है। उन्हें उत्तर भारत के मुकाबले कमजोर करने की कोशिश हो रही है।विपक्ष ने इस माहौल को खत्म कर दिया। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए यह विपक्ष का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री महिलाओं की आड़ में अपने राजनीतिक उद्देश्य छुपाना चाह रहे थे। 12 साल बाद भी उन्हें दक्षिण में स्वीकृति नहीं मिली। इसके लिए वाजपेयी की तरह वहां की पार्टियों का नेताओं का विश्वास जीतकर धीरे–धीरे जगह बनाते। लेकिन उन्होंने सीधे दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें कम करने का षड्यंत्र रच डाला। राहुल ने पकड़ लिया। क्या इंटेलिजेंट कहानी थी। एकदम सामयिक। जो लोग उस समय लोकसभा में थे वही समझ सकते हैं कि सरकार के मंत्रियों और खुद लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल को किस तरह यह कहानी सुनाने से रोकने की कोशिश की। बाहर तो जितना लिमिटेड संसद टीवी से आता है वही दिख रहा था। मगर अंदर प्रेस गैलरी से वह सब दिख रहा था कि किस तरह राहुल का मजाक उड़ाने से लेकर चिल्लाकर उन्हें रोकने, बार–बार व्यवधान करने याने कि हर तरह डिस्करेज करने की कोशिश हुई। राहुल को कई बार बैठ जाना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ने मर्यादा का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। यहां तक बोल गए ओम बिरला कि अगर सत्ता पक्ष इन्हें नहीं रोकेगा तो मैं रोकूंगा। और सबसे मजेदार बात यह कि राहुल ने एक बार भी प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मोदी नाम लेना तो दूर की बात। केवल मैजिशियन कह रहे थे। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। राहुल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लिया। मगर सत्ता पक्ष कहता रहा कि मोदी की तुलना जादूगर से करना प्रधानमंत्री का अपमान है। जिनकी समझ में नहीं आ रहा था उनकी भी आ गया कि राहुल मोदी का जादू खतम होने की बात कर रहे हैं। और शनिवार रात को उनके भाषण के बाद उनके समर्थक भी मान गए कि जादू खत्म हो गया। शब्दों का खोखलापन उजागर हो गया। बहुत नाटकीय भाव भंगिमाएं बनाने की कोशिश की मगर दर्शकों में कोई भावनाएं नहीं जगा पाए। अब बंगाल और तमिलनाडु में मतदान होना है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में पूरा और बंगाल के पहले फेज का। शनिवार को प्रधानमंत्री इसलिए बार–बार शायद 8–10 बार तो लिया होगा टीएमसी और डीएमके का नाम लिया। इतनी ही बार और ले लेते मगर फिर भी कुछ नहीं होता। तमिलनाडु में कहीं मुकाबले में ही नहीं हैं। बंगाल में भी हार पक्की है। मोदी की आखरी कोशिश बंगाल पर ही टिकी है।

नए भारत की एमएसएमई क्रांति के केंद्र में है नारी शक्ति

शोभा करंदलाजे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभाओं में एक–तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सितंबर 2023 में संसद में समर्थन करते हुए विश्वास व्यक्त किया था कि भारत तभी आगे बढ़ सकता जब देश की नारियां भी इसके साथ ही उन्नति करें। उनका यह विश्वास एमएसएमई क्षेत्र (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) में सरकार के काम में हर रोज दिखाई देता है। एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसके दिल में महिला उद्यमियों का मूक बल बसता है। आखिरकार आज इस मूक बल को वह राष्ट्रीय मान्यता, संस्थागत समर्थन और नीतिगत गति मिल रही है जिसका वह हमेशा से हकदार है। आँकड़े बयां करते हैं कहानी भारत के एमएसएमई इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 2026 की शुरुआत तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 3.11 करोड़ से अधिक महिला–नेतृत्व वाले उद्यम पंजीकृत हुए हैं। वास्तव में, उद्यम और उद्यम असिस्ट पंजीकरण के अनुसार, देश के कुल पंजीकृत एमएसएमई में महिला–स्वामित्व वाले उद्यमों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है और ये रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिला उद्यमियों के लिए सबसे प्रभावशाली सुधारों में से एक उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज रहित और स्व–घोषणा पर आधारित इस व्यवस्था ने उस नौकरशाही बाधा को समाप्त कर दिया, जो महिलाओं के लिए एक बड़ी रुकावट बनी हुई थी। जनवरी 2023 में शुरू किए गए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ने अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत उन महिलाओं तक पहुँच बनाकर इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया, जिनके पास शपैन्च नंबर या जीएसटीएन नहीं था। इसने उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण और सरकारी योजनाओं के लाभों के दायरे में लाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं को सशक्त बनाना केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीति है। उन्होंने ही कहा था कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार सशक्त होते हैं और जब परिवार सशक्त होते हैं, तो राष्ट्र निरंतर मजबूत होता जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीतिक क्षेत्र में इस दर्शन की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता एक व्यापक और बहुआयामी नीतिगत ढांचे के रूप में सामने आई है, जो ऋण, कौशल, बाजार तक पहुंच, पहचान और गरिमा जैसे पहलुओं को समाहित करती है। ये सभी मिलकर, आपूर्ति पक्ष पर आठ मुख्य श्रेणियों के माध्यम से उद्यमियों को सहायता प्रदान करते हैंरू तकनीक तक पहुँच, ऋण और वित्त तक पहुँच, डिजिटलीकरण को बढ़ावा, अवसरंचना सहायता, औपचारिकीकरण और समावेशन, बाजार तक पहुँच, और उद्योग–स्तरीय कौशल विकास। पिछले पाँच वर्षों में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 3.2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को सहायता दी गई है। हाल के आँकड़ों के अनुसार, पीएमईजीपी के कुल लाभार्थियों में से 39त्न महिलाएँ हैं जो इस योजना की रूपरेखा और महिलाओं की कुछ कर दिखाने की ललक, दोनों को दर्शाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट महिला ऋणदाताओं को 90 प्रतिशत तक का बढ़ा हुआ गारंटी कवर प्रदान करता है। इससे बैंक बिना कुछ गिरवी रखे महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक खरीद नीति में संशोधन कर यह अनिवार्य किया गया कि केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत हिस्सा महिला–स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से ही खरीदें। इससे महिला उद्यमियों के लिए एक सुनिश्चित और अनुमानित बाजार तैयार होता है, जिससे सरकारी खर्च को महिलाओं के व्यवसाय की वृद्धि में बदला जा रहा है। यह देखकर खुशी होती है कि वित्त वर्ष 2025–26 में, केंद्रीय मंत्रालयोंधविभागोंध्केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कुल खरीद का 3.5 प्रतिशत हिस्सा महिला एमएसएमई से ही खरीदा गया था।

विकास और सुशासन के मुद्दों पर भी काम करे मीडिया

प्रो. संजय

मीडिया की ताकत आज सर्वव्यापी है और कई मायनों में सर्वग्रासी भी। ऐसे में विकास के सवालों और उसके लोकव्यापीकरण में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो उठी है। यह एक ऐसा समय है, जबकि विकास और सुशासन के सवालों पर हमारी राजनीति में बात होने लगी है, तब मीडिया में यह चर्चाएं न हों यह संभव नहीं है। समाज विकास की प्रक्रिया और उसकी आकांक्षाएं मीडिया में दर्ज हों, ऐसी उम्मीद की जाती है। इन विषयों की रिपोर्टिंग के लिए तमाम पत्रकार आगे आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी विकास की पत्रकारिता को एक नई नजर से देखा जा रहा है। भारत में विकास की पत्रकारिता और उसके सवालों से जूझने के लिए पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार है, किंतु मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा इन विषयों को तरजीह न दिए जाने के कारण निराशा ही हाथ लगती है। संकट पत्रकारों की ओर से नहीं, मीडिया संस्थानों और प्रबंधकों की ओर से है। विकास का मुद्दा क्या सिर्फ सरकारी विज्ञापनों का विषय है, सरकारी मीडिया का विषय है, या यह समाज में हो रहे नवाचारों का भी विषय है। विकास पत्रकारिता को पाठ्यक्रम के साथ मीडिया कर्म का भी हिस्सा होना चाहिए। भारत जैसे विविधता और बहुलता भरे समाज में सभी उम्मीदों, सपनों और बदलावों को रेखांकित कर पाना कठिन है। क्योंकि विकास के अनेक तल हैं और देश में समाज की रचना भी बहुस्तरीय है, देश में कहावत प्रचलित है 'चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर वाणी' , इसलिए किसी राज्य को भी एक ही पैमाने से नहीं नापा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश में एक तरफ समृद्ध मालवा है, तो दूसरी और झाबुआ जैसे इलाके भी हैं। एक तरफ इंदौर की चमक है, तो दूसरी ओर अलीराजपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ है, तो भिलाई भी है। ऐसे में पत्रकारों या विकास के सवालों पर लिखने वालों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह विकास की भूमिका भी यहां विस्तृत और परिवर्तित हो जाती है। हम देखें तो 1950 के पहले आर्थिक विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। किंतु 1950 के बाद की चिंताएं अलग हो गयी। बाद के दिनों में सामाजिक विकास को एक बड़ा कारक माना जाने लगा है। सामाजिक न्याय से लेकर स्थाई विकास के सवाल अब बड़े हो गए हैं। यहां तक कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें भी हमारे सामने हैं। एक समय में विकसित और विकासशील देशों की बहसें भी हमने सुनीं जिनमें मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट एक अलग तरह से बात करती हुयी नजर आती है, जिनमें कुछ सवाल आज भी मौजू हैं। नियंत्रित मीडिया से मीडिया के चौतरफा विकास का समय भी आया जिसमें कुछ भी छिपाना और दबाना असंभव सा हो गया। कई बार यह भी लगता रहा कि विकास का सवाल सिर्फ सरकारी माध्यमों (मीडिया) के लिए ही महत्व का है, बाकी माध्यमों का अपना एजेंडा और राय अलग है। यहां यह भी देखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन(संचार) सिर्फ सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं है। बल्कि पक्षधरता के साथ, न्याय के लिए खड़ा होना भी है। जन को ताकतवर बनाना भी है। अवसर की समानता की अवधारणा को प्रचारित और स्थापित करना भी है। विकेन्द्रीकरण ने विकास के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। जिनके भी ठोस और वाजिब हल हमें ढूंढने चाहिए। जैसे पंचायती राज में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। सत्ता इसके चलते पंचायतों तक पहुंची, पर सवाल यह है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है? क्या संसदीय राजनीति और चुनावों की तमाम बुराईयां हमारी पंचायतों तक नहीं पहुंच गयी? वहीं हम मीडिया को देखें तो उसका भी विस्तार हुआ है। व्यापकता बढ़ी है, पहुंच भी बढ़ी है। पर सवाल यह है कि क्या मीडिया में संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता और विविधता को आदर देने की उसकी भावना भी बढ़ी है, तो शायद उत्तर नकारात्मक ही हो। तीनों तंत्रों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) से निराश लोग मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं। कई अर्थों में सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण दिखता है, किंतु मीडिया धीरे–धीरे केन्द्रीकरण का शिकार हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्रास मीडिया ओनरशिप के बारे में भी भारत जैसे देश सोचें। ताकि मीडिया के एकाधिकार के खतरों से बचा जा सके। इसके साथ ही प्रेस कौंसिल जैसी नख–दंत हीन संस्था के अधिकारों और क्षेत्राधिकार में बदलाव करते हुए उसे मीडिया कौंसिल में बदला जाना जरूरी है ताकि वह आज के प्रभावी मीडिया को भी अपनी चर्चा में ले सके।संचार व मीडिया अध्ययन हम जिस संकट से दो चार हैं, वह यह है कि सूचनाएं बढ़ गई हैं और खबरें घट गई हैं। अखबारों के पन्ने बढ़ गए हैं, किंतु इनसे आम–आदमी गायब है। चौनल अब चौबीस घंटे कुछ बोलते हैं, पर उनमें विकास और जनता के सवालों की जगह बहुत कम है। जबकि विकास की पत्रकारिता की मुक्ति इसमें है कि जो लोग मीडिया तक नहीं पहुंच सकते, मीडिया उन तक पहुंचे। उनका दर्द सुने। अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबरों की ओर जाएं। हमारी राजनीति बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है किंतु हमारे मीडिया के सोचने और अभिव्यक्त करने की शैली उस तुलना में नहीं बदली जैसी बदलनी चाहिए। आज यह मान्यता बन चुकी है कि विकास भारतीय मीडिया की प्राथमिकता नहीं है, शायद समाज भी उसकी प्राथमिकता नहीं है। हमारे नागरबोध ने मीडिया को समाज से बड़ा बना दिया है। किंतु यह तय मानिए कि कोई भी मीडिया, कोई भी राजनीति और कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। 18 से 25 साल और 18 से 35 साल के युवाओं के बीच बाजार खोज रहे मीडिया की चिंताएं अलग हो सकती हैं किंतु समाज की चिंताएं कुछ भिन्न हैं। वे ही वास्तविक चिंताएं हैं। मीडिया अगर इन चिंताओं से अलग व्यवहार कर रहा है तो वह अपने अस्तित्व पर संकट स्वयं रच है। विश्वसनीयता और प्रामणिकता के संकट तो उसके साथ संयुक्त हैं ही। मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह सोचने का सही समय है कि जब सारा देश विकास और सुशासन के सवालों पर गंभीर हो रहा है, उसमें अपने शासकों से जवाब मांगने की हिम्मत आ रही है, तो हमारा मुख्यधारा का मीडिया क्या कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के सामने आज उपस्थिति हैं, अगर इन सवालों के हल हमने आज नहीं तलाशे तो कल बहुत देर हो जाएगी।

महिला आरक्षण पर सरकार का खेल

सत्यमेव जयते, यह भारत का ध्येय वाक्य है। भारतीयों का यही यकीन है कि सच की ही जीत होती है। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार बार–बार हमारे इस यकीन की परीक्षा ले रही है। देश में अब एक बार फिर सच को नकारने की कोशिश और झूठ को बढ़ावा देने की राजनीति शुरु हो गई है। शनिवार का प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन ऐसी ही एक कोशिश थी। संसद के विशेष सत्र में 131 संविधान संशोधन विधेयक को सरकार पारित नहीं करवा सकी। इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने मोदी सरकार को करारी हार का स्वाद चखाया तो अब भाजपा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर है कि वह नारी का अपमान करती है। हालांकि संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष ने लगातार यही कहा कि उसका विरोध महिला आरक्षण से नहीं हैजब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी सरकार लाई थी, जिसके जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, तो सारे दलों ने इस पर सहमति जताई थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस सफलता के लिए अपनी पीठ थपथपाई थी, तो अब उनके द्वारा लाया गया एक दूसरा विधेयक पारित नहीं हो सका, तो इस की जिम्मेदारी भी उन्हें खुद लेनी चाहिए, मगर वे विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे हैं।यह बात उसने पहले ही साफ कर दी थी, फिर भी सरकार ने विधानसभा चुनावों के बीच में संसद का विशेष सत्र लगाया, ताकि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करवा सकें, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में ही सरकार के हाथ नाकामी लगी, तो अभी के लिए बाकी दोनों विधेयकों से किनारा कर लिया गया। सरकार ने 2023 में पारित विधेयक पर तो कानून नहीं बनाया, लेकिन अब चाहती है कि बिना जनगणना के परिसीमन हों, जिसमें संसद और विधानसभा की सीटें बढ़ जाएं, उसके बाद उसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया जाए। लेकिन विपक्ष का तर्क था कि महिलाओं को आरक्षण आप अभी दे दीजिए, उसके लिए परिसीमन की जरूरत नहीं है। असल में मोदी सरकार की निगाहें 2029 के चुनावों पर हैं, जिसमें परिसीमन के बाद उत्तरभारत की सीटें दक्षिण भारत की तुलना में बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहां आबादी ज्यादा है और दक्षिण भारत में जनसंख्या पर काफी हद तक नियंत्रण है। भाजपा को उत्तरभारत से ही फायदा है। लेकिन इस बार मोदी सरकार की चालाकी नाकाम हो गई। राहुल गांधी ने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान जिस तरह जादूगर का खेल खराब होने की कहानी सुनाई और उस पर सत्तापक्ष के लोग हड़बड़ाए, घबराए दिखे, उसी से समझ आ गया कि उन्हें भी हार का डर था। हालांकि हारने के बाद भी भाजपा ने जब विपक्ष को ही महिला–विरोधी साबित करने की कोशिश की और मीडिया इसमें रूदाली की भूमिका में आ गया, तो प्रियंका गांधी ने शनिवार सुबह एक प्रेस कांफ्रेंस कर सारी स्थिति साफ कर दी कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, उसके नाम पर अभी परिसीमन कराने की कोशिश के विरोध में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का मसीहा बनना आसान नहीं होता। उसके लिए काम करना पड़ता है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने संसद में यह भी कहा था कि बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। लेकिन नरेन्द्र मोदी की समझ में शायद इनमें से एक भी बात नहीं आई और उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस का जवाब देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें मणिपुर में भड़कती हिंसा, ईरान के कारण ऊर्जा संकट, भारतीय झंडे वाले जहाज पर ईरानी नेवी का हमला, अर्थव्यवस्था का डांवाडोल होना, ऐसे किसी जरूरी मुद्दे पर बात नहीं की, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए महिला आरक्षण लागू न करने के लिए विपक्ष को कोसा।प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए देश की श्माताओं और बेटियोंश से माफी मांगी और विपक्ष पर श्छोटी राजनीतिश के कारण महिलाओं के सपनों को कुचलने का आरोप लगाया। अपने करीब आधे घंटे के संबोधन में कम से कम 34 बार तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नाम लिया, यानी औसतन हरेक मिनट में कांग्रेस कहा, उसके अलावा सपा, डीएमके, टीएमसी सबकी बुराई की। अब उन्हें इतना ही दुख है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो विपक्ष जो कह रहा है कि 2023 में पारित विधेयक को ही लागू कर दीजिए, तो इस बात को श्री मोदी क्यों नहीं मान रहे हैं। और विपक्ष के सामने खुद को इतना ही मजबूर समझ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी की तरह लोकसभा भंग कर फिर से बहुमत लाने का साहस दिखाइए। ध्यान रहे कि सितंबर 1970 में प्रिवीपर्स खत्म करने वाला विधेयक राज्यसभा में मात्र एक वोट से गिर गया था। इस हार के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी थी। स्वतंत्र भारत में यह पहली बार था जब लोकसभा भंग की गई थी। तब इंदिरा गांधी ने इसी तरह देश को संबोधित किया और अपने प्रसारण में कहा, श्हम केवल सत्ता में बने रहने को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि उस सत्ता का उपयोग अपनी जनता के विशाल बहुमत के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए करना चाहते हैं।य इसके बाद 1971 में मध्यावधि चुनाव हुए।

संक्षिप्त खबरें

अग्निकांड पर भ्रामक पोस्ट करने वाला सिविल इंजीनियर गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। विकासनगर के सेक्टर–12 में 15 अप्रैल को हुए अग्निकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर गलत व भ्रामक सूचनाएं पोस्ट करने वाले सिविल अभियंता सुधाकर त्रिपाठी को रविवार को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में दो अलग–अलग प्राथमिकी दर्ज की थीं। थाना प्रभारी विकासनगर आलोक सिंह ने बताया कि दरोगा अतुल कुमार और दरोगा भानु प्रताप सिंह ने ये प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। इन प्राथमिकियों में लोगों में आक्रोश पैदा करने और पुलिस के प्रति भड़काने का आरोप था। साइबर क्राइम सेल की मदद से भ्रामक पोस्ट करने वालों को चिह्नित किया गया। इसी क्रम में विकासनगर निवासी सुधाकर त्रिपाठी को पकड़ा गया। सुधाकर मूल रूप से चित्रकूट के पहाड़ी थानाक्षेत्र का रहने वाला है और निजी कंपनी में काम करता है। पूछताछ में उसने ऑनलाइन मंच पर गलत पोस्ट करने की अपनी गलती स्वीकार की है। एसीपी गाजीपुर ए. विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस और साइबर क्राइम सेल की टीम अन्य लोगों को भी चिह्नित कर रही है। इन लोगों ने अग्निकांड पर सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट अपलोड की थीं। सोशल मीडिया सेल सभी प्लेटफॉर्म की निगरानी कर रहा है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

गोमती नदी में नहाने गए युवक की डूबकर मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में गोमती नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत हो जाने का दुखद मामला सामने आया है। युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, जहां गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तलाश अभियान शुरू किया, जिसके बाद दूसरे दिन युवक का शव बरामद कर लिया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 18.04.2026 को सूचना मिली कि आदिल पुत्र टिंकू (उम्र लगभग 18 वर्ष) निवासी के.के. सिंह नगरध संजोग नगर, थाना हुसैनगंज, जनपद लखनऊ, अपने कुछ साथियों के साथ गोमती नदी में पीपा पुल, मेंहदी घाट के पास (थाना ठाकुरगंज क्षेत्र) नहाने गया था। नहाते समय युवक अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते नदी में डूब गया। उसके साथ गए अन्य साथी किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन आदिल का पता नहीं चल सका।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत एवं बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंच गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम द्वारा नदी में युवक की तलाश के लिए व्यापक स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। देर शाम तक चले प्रयासों के बावजूद पहले दिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका, जिसके बाद अगले दिन भी खोजबीन जारी रखी गई।काफी प्रयासों के बाद आज दिनांक 19.04.2026 को रेस्क्यू टीम को सफलता मिली और युवक का शव गोमती नदी से बरामद कर लिया गया। शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया और परिवार के सदस्यों का रो–रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने तत्काल परिजनों को घटना की सूचना दे दी।पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए।

राजधानी में संपन्न हुआ आईआईएमसी एलुमनी मीट, याद किए गए प्रदीप मिश्रा

लखनऊ, (संवाददाता)। आईआईएमसी एलुमनाई एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश चौप्टर का सालाना मिलन कार्यक्रम श्कनेक्शन्सश रविवार को राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मिश्रा के निधन पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जो भारतीय जन संचार संस्थान के पूर्व छात्र थे। वक्ताओं ने पत्रकारिता में उनके योगदान और उनसे जुड़ी यादें साझा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौप्टर अध्यक्ष मणेन्द्र मिश्रा ने की, जिसे दिल्ली से आए इमका के पूर्व अध्यक्ष प्रसाद सान्याल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रभाष झा, महासचिव अतुल गुप्ता के अलावा चौप्टर के पूर्व अध्यक्ष संतोष वाल्मीकि, महासचिव पंचानन मिश्रा, कमलेश राठौर, भाई शैली, आलोक कुमार, प्रियंका सिंह, विवेक शुक्ला, अर्चना सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एलुमनी सम्मिलित हुए और संगठन की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर विशाल शुक्ला और हर्षित आजाद गुप्ता को सर्वसम्मति से यूपी चौप्टर का सचिव चुना गया।

अग्निकांड पर सियासत तेज, भाजपा ने अखिलेश यादव पर लगाए आरोप

लखनऊ, (संवाददाता)। विकासनगर में हुए अग्निकांड पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव व उनके सहयोगियों पर आरोप लगाए हैं। भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण प्रताप सिंह, अविनाश यादव व अन्य ने विकासनगर थाने में तहरीर दी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भ्रामक आरोप लगाने व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। 15 अप्रैल को सेक्टर–12 की झुग्गी बस्ती में आग लगी थी। सपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना को साजिश बताया था। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाए थे। भाजपाइयों का कहना है कि इन बयानों से उनकी छवि धूमिल हुई है। एसीपी गाजीपुर ए विक्रम सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है।

शहर से गांव तक बिजली के लिए त्राहि-त्राहि

लखनऊ, (संवाददाता)। शहर से गांव तक अलग–अलग इलाकों में शनिवार आधी रात से लेकर रविवार रात तक बिजली के लिए त्राहि–त्राहि मची रही। कई इलाकों में भीषण गर्मी के दौरान पूरी रात बिजली गुल रहने से लोग ठीक से सो भी नहीं सके। यह बिजली संकट एरियल बंच्ड केबल (एबीसी) फुंकने और फॉल्ट के कारण उत्पन्न हुआ। जानकीपुरम के गोड़ियनपुरवा में शनिवार आधी रात को एबीसी में आग लगने के कारण सुबह तक बिजली आपूर्ति ठप रही। कर्मचारी पूरी रात केबल बदलने के लिए काम करते रहे, इसके बावजूद काफी बड़े इलाके की आबादी रात को सो नहीं सकी। चौक के विक्टोरिया उपकेंद्र से अकबरी गेट सहित बड़ा इलाका शनिवार आधी रात के बाद तक बिजली संकट से जूझता रहा। यहां पर भूमिगत केबल में फॉल्ट आ गया था जिसे सही करने के लिए कर्मचारी को नाले में सीढ़ी के सहारे उतरना पड़ा।

पूर्व मंत्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना' को नम आंखों से अंतिम विदाई, कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में यूपी प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना' के निधन पर पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार को उनके पैतृक आवास रामनगर कोट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मौके पर पहुंच कर उनकी आत्मा को शांति ले लिय प्रार्थना करते हुए परिजनों को ढाढस बध ाया।और कहा कांग्रेस पार्टी ने अपना एक बेहतरीन सिपाही खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। हम लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह, शहर अध्यक्ष आरिफ खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पार्टी का तिरंगा चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। शोकसभा में नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें पार्टी का सच्चा सिपाही बताया। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना' का पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने छात्र राजनीति और यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अपने समर्पण व संघर्ष के बल पर प्रदेश स्तर तक पहचान बनाई। उन्होंने रारी विधानसभा क्षेत्र से विध ायक रहते हुए जनता की सेवा की और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने यह भी बताया कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद वर्ष 2003 में वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बने और संगठन को मजबूती प्रदान की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि पार्टी ने एक बेबाक और स्पष्टवादी नेता खो दिया है। उनका जीवन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित था और वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले नेता रहे। प्रदेश सचिव सत्यवीर सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अरुण कुमार सिंह के निधन से कांग्रेस ने एक मजबूत स्तंभ खो दिया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था और वे हमेशा कार्यकर्ताओं व जरूरतमंदों के लिए तत्पर रहते थे। इस अवसर पर सेवादल के मुख्य जिला संगठक आरिफ सलमानी, जिला उपाध्यक्ष शेर बहादुर सिंह, इरशाद खान, जब्बार अली सलमानी, महिला अध यक्ष रेखा सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमारी मिश्रा, अतुल सिंह, नगर अध्यक्ष निशु केसरी, चंद्रशेखर शुक्ला, जय प्रकाश कंकड़ी, घनश्याम मिश्रा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल गमगीन रहा और उपस्थित लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी।

जौनपुर में श्रीमद्भागवत कथा से पहले निकली भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं से गूंजा नगर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में मंगलवार को सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा प्रवचन कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व भव्य शोभायात्रा निकाली गई। नैमिषारण्य (सीतापुर) स्थित सनातन उत्थान फाउंडेशन के संस्थापक शिवानंद भाई श्री महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों वाहनों के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे नगर का भ्रमण किया। इस दौरान जयकारों और भजन–कीर्तन से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा बीआरपी मैदान से प्रारंभ होकर लाइन बाजार, बाजिदपुर तिराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, ओलंदगंज, चहारसू चौराहा और कोतवाली होते हुए पुनः बीआरपी मैदान पहुंची। जगह–जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। आयोजकों के अनुसार बुध वार से सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा प्रवचन कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। कथा प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं, कथा से पूर्व प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रीकृष्ण नाम महामंत्र यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर शिवानंद भाई श्री महाराज ने कहा कि सत्संग मानव के चरित्र निर्माण की महत्वपूर्ण पाठशाला है। उन्होंने कर्म और उसके फल पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मनुष्य हर समय कर्म करता है और उसके हर कर्म का फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। 'अवश्यमेव भोक्तव्यम' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाराज ने धर्म के महत्व को बताते हुए कहा कि भौतिक साध नों से केवल सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन सच्चा आनंद केवल भगवत कृपा से ही मिलता है। धर्मशील जीवन जीने वाले व्यक्तियों के जीवन में आनंद स्वतः ही आ जाता है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाते हुए कहा कि आत्मा परमात्मा का अंश है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह उनके शोभा यात्रा को रोककर उनकी आरती उतारी गई।और लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया बड़ी संख्या में लोगों के कथा में शामिल होने की संभावना है।

सम सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय सख्त, कॉलेजों को जारी किए कड़े निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टर परीक्षाओं के सुचारु और पारदर्शी संचालन को लेकर संबद्ध महाविद्यालयों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आंतरिक एवं प्रायोगिक अंक समय से अपलोड न करने, केंद्राध्यक्ष नियुक्त न करने और सीसीटीवी मॉनिटरिंग से न जुड़ने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंगलवार को विश्वविद्यालय के सीसीटीवी मॉनिटरिंग कक्ष से कुलपति प्रो. वंदना सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव केशलाल और प्रो. मनोज मिश्र ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का ऑनलाइन निरीक्षण किया। वहीं परीक्षा नियंत्रक ने जौनपुर के केडीएस महाविद्यालय और श्रद्धा शंकर महिला महाविद्यालय का भौतिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भीषण गर्मी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त पेयजल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पंखों और रोशनी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कुलपति ने स्पष्ट किया कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय ने बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी (एग्रीकल्चर), बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों के आंतरिक व प्रायोगिक अंक अपलोड न करने वाले कॉलेजों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 23 अप्रैल 2026 तक अंतिम समय सीमा निर्धारित की है। चेतावनी दी गई है कि समय से अंक अपलोड न करने पर संबंधित महाविद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जिन कॉलेजों ने अभी तक अपने केंद्रों को सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल से नहीं जोड़ा है या केंद्राध्यक्ष नियुक्त नहीं किए हैं, उन्हें भी 23 अप्रैल तक का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर नियमानु सार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

सहायक आचार्य पुनर्परीक्षा छह जनपदों में सकुशल सम्पन्न

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या–51) के 16 विषयों की लिखित पुनर्परीक्षा रविवार को प्रदेश के छह जनपदों में सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गई। यह परीक्षा आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर एवं वाराणसी के कुल 50 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली पूर्वान्ह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 02:30 बजे से 04रू30 बजे तक संचालित की गई।आयोग में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से आयोग के अध्यक्ष डॉ० प्रशान्त कुमार, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव की उपस्थिति में सभी परीक्षा केन्द्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा केन्द्रों पर लगाए गए कैमरों के माध यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर सतत नजर रखी गई। प्रदेश के सभी केन्द्रों पर परीक्षा नकलविहीन, शुचितापूर्ण, समयबद्ध तथा निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हुई।आयोग के अध्यक्ष एवं वरिष्ठतम सदस्य द्वारा प्रयागराज के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही आयोग द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल के तहत पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत प्रयागराज के निर्धारित पांच परीक्षा केन्द्रों पर प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त उत्तर पत्रकों की उनके परीक्षा कक्षों में ही कक्ष निरीक्षक एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति है।

भाजपा के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें, कार्यकर्ता संयम बरतें- अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का व्यवहार भाजपा की तरह नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक में हार के बाद भाजपा में बौखलाहट और हताशा है तथा विपक्ष, विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्र के तहत विरोध कराया जा रहा है।अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि भाजपा के भ्रामक और दूषित प्रचार का जवाब देने में संयम बरतें तथा धरना–प्रदर्शन से बचें। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की महिलाओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन बनाए रखते हुए भाजपा की साजिशों और षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए।अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर भ्रांतियां और झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि आधी आबादी में 66 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्गों की है और समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया पिछड़ों में महिलाओं को भी शामिल करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को उचित स्थान नहीं देना चाहती और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के नाम पर अपनी मनमानी करना चाहती है।उन्होंने कहा कि अब पार्टी का ध्यान पूरी तरह उत्तर प्रदेश पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा, इसलिए प्रदेश को भाजपा के प्रभाव से मुक्त कराना जरूरी है।अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी भाजपा शासन में लगातार बढ़ रही है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि खाद, बीज और कीटनाशकों की समस्या से किसान परेशान हैं और आम लोगों के जीवन में कठिनाइयां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता से हटने पर ही प्रदेश में खुशहाली आएगी और महिलाओं, किसानों तथा नौजवानों को राहत मिल सकेगी।

नहरें सूखीं, जायद की फसलें संकट में

लखनऊ, (संवाददाता)। भीषण गर्मी के बीच शारदा सहायक खंड 28 हैदरगढ़ ब्रांच से निकलने वाली नहरें इन दिनों सूखी पड़ी हैं। ये हालात ऐसे समय में हैं जब जायद की फसल, हरे चारे और मेंथा को सिंचाई के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नहरों में पानी न होने से किसान परेशान हैं। क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा होने के बावजूद किसानों को निजी पंपसेटों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत लगातार बढ़ रही है। अमेठियन पुरवा के किसान मुन्नू सिंह ने बताया कि उनके खेत में मेंथा की फसल खड़ी है वहीं जानवरों के लिए हरा चारा भी बोया गया है। सिंचाई के लिए वे नहरों के पानी पर निर्भर थे, लेकिन नहर सूखी होने से उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में उन्हें महंगे किराये पर पंपसेट लेकर सिंचाई करनी पड़ रही है। मुकुंद खेड़ा के मलखानसिंह का कहना है कि उनकी मेंथा की फसल भी पानी के अभाव में प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि मार्च से ही नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, फिर भी अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसानों का कहना है कि समय पर सिंचाई न होने से फसल की पैदावार पर असर पड़ना तय है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस संबंध में शारदा सहायक खंड 28 हैदरगढ़ के अधिशासी अभियंता नवनीत सिंह ने बताया कि नहर का पानी लखीमपुर हेड से बंद है। फिलहाल विभाग की प्राथमिकता तालाबों को भरने की है। संभावना है कि मई में नहरों में पानी छोड़ा जाएगा।

रिक्शा पर अचेत अवस्था में मिला चालक, मौके पर ही मौत पहचान के प्रयास जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजध ानी में रविवार को एक रिक्शा चालक अपनी रिक्शा पर अचेत अवस्था में मिला, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृत घोषित किया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और उसकी शिनाख्त के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 19.04.2026 को समय लगभग 10रू30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक रिक्शा चालक अपनी रिक्शा पर अचेत अथवा मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति रिक्शा पर ही निश्चल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसकी जांच करने पर उसके मृत होने की पुष्टि हुई।घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों में हलचल मच गई। पुलिस ने मौके पर उपस्थित आसपास के लोगों तथा अन्य रिक्शा चालकों से मृतक की पहचान के संबंध ा में पूछताछ की, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा मृतक के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा सकी। इसके चलते पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त के लिए अन्य माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं।पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की। पंचायतनामा की कार्यवाही संपन्न करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सके। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया किसी बाहरी चोट की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मृत्यु के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

दूध उत्पादन में पश्चिमी यूपी अव्वल, बुंदेलखंड पीछेय बुलंदशहर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक जिला

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश 50 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। इसमें बुलंदशहर पूरे प्रदेश में नंबर एक है। वहीं, बुंदेलखंड पांच से सात फीसदी की हिस्सेदारी के साथ बहुत पीछे है। अब प्रदेश सरकार की ओर से हर जिले में पर्याप्त दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बड़ी डेयरी के साथ ही छोटी डेयरी का भी विकास किया जाएगा। संबंधित क्षेत्र की जलवायु के अनुसार उन्नत किस्म की भैंस और गाय की नस्ल को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में सहकारी समितियों के साथ ही निजी कंपनियां भी गांव–गांव दुग्ध कलेक्शन सेंटर खोल रही हैं। यहां 10 वर्ष में करीब 40 फीसदी की बढोत्तरी के साथ दूध उत्पादन करीब 388 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। कुल उत्पादन में करीब 50 फीसदी हिस्सेदारी अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। बुलंदशहर में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। इसी तरह पूर्वांचल की हिस्सेदारी करीब 31 फीसदी, मध्य यूपी की 14 फीसदी और बुंदेलखंड की पांच से सात फीसदी ही है। इस अंतर को कम करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत करीब एक हजार करोड़ खर्च करके जिलेवार दूध उत्पादन और आपूर्ति की चेन विकसित की जा रही है। बुलंदशहर में दूध का सहकारी और निजी दोनों तरह का नेटवर्क है। दिल्ली, एनसीआर से नजदीकी उत्पादकों को अच्छा मुनाफा दिलाती है। यहां की जमीन चारा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। यहां मुर्रा भैंस और शाहीवाल गाय पर अधिक जोर है। अब इस नस्ल को प्रदेश के अन्य हिस्सों की डेयरी में भी पहुंचाया जा रहा है। बुंदेलखंड में कम पानी की वजह से चारे का संकट रहता था। ऐसे में यहां दूध उत्पादन कम रहा है, लेकिन अब नस्ल सुधार के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। यहां दूध उत्पादक कंपनियां लगी हैं। अभी सात जिलों में प्रतिदिन करीब 2.30 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का नया प्लांट लगाया जाएगा। झांसी में चल रहे 10 हजार लीटर क्षमता के प्लांट को विस्तारित करके 30 हजार लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। प्रदेश में डेयरी कारोबार से करीब चार लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। प्रदेश सरकार की ओर से समूह में यह कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

शीतल पेयजल की टोटी से गर्म जल निकलने से रेल यात्री परेशान

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर स्थित रेल यात्रियों को इस समय भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए रेल विभाग द्वारा शीतल जल की टोटियां तो लगी है लेकिन वह निष्प्रोज्य ही दिखाई दे रही है। इसका खुलासा उसे समय हुआ जब रेल यात्री इन टोटियों से पानी का उपयोग करते दिखे पूछने पर बताया कि इन टोटियों से भी गर्म पानी ही निकल रहा है।जबकि जानकारों की माने तो इसमें से ठंडा पानी निकालना चाहिए लेकिन इस समय भीषण गर्मी के दौरान भी रेल यात्रियों को शीतल जल नहीं मिल रहा है जिसके चलते दूर दराज से आने जाने वाले रेल यात्रियों को गर्म पानी ही पीने को मिल रहा है। यही दशा प्लेटफार्म नंबर पर भी है। जिसके चलते इधर से गुजरने वाले रेल यात्रियों का मानना है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ अव्यवस्था ही दिखाई दे रही है। जिसके चलते रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है परंतु इस गंभीर समस्या पर संबंधित रेल विभाग के अधिकारी हुआ कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे।

शशांक त्रिपाठी बने अयोध्या जिले के नए डीएम

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। बाराबंकी मे जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी अब अयोध्या जनपद के नए जिला अधिकारी होंगे।जबकि अभी तक अयोध्या जनपद के जिलाधिकारी रहे निखिल टीकाराम फुंडे का स्थानांतरण मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।बताते चले कि नवागत डीएम शशांक त्रिपाठी इससे पहले पड़ोसी जनपद बाराबंकी में जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे।देखा जाये तो उन्होंने सीतापुर में सहायक मजिस्ट्रेट, रायबरेली में जॉइंट मजिस्ट्रेट और गोंडा में मुख्य विकास अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।इसके अलावा वे मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी रह चुके हैं। मालूम हो कि बाराबंकी में जिलाधिकारी रहते हुए शशांक त्रिपाठी ने कई नये पहल की शुरूआत किया।।वर्ष 2025 में छात्राओं को एक दिन के लिए डीएम बनाकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया।वहीं, जलभराव और साफ–सफाई की समस्याओं को लेकर वे स्वयं सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करते नजर आए,जिससे उनकी सक्रिय और संवेदनशील कार्यशैली की झलक मिली।जबकि अयोध्या जनपद में डीएम रहे टीकाराम फुंडे को पिछले वर्ष 16 अप्रैल को अयोध्या का जिलाधिकारी बनाया गया था।अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य कराए।14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण से लेकर राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना जैसे कार्यों में उनकी अहम भूमिका रही। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता की समस्याओं को निष्पक्ष रूप से सुनकर समाधान करने की दिशा में भी प्रभावी कार्य किया।डीएम निखिल फुंडे की कार्यशैली और विकास कार्यों के चलते उन्होंने अयोध्या में अपनी अलग पहचान बनाई है।अब मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है,जिससे उनके अनुभव का लाभ प्रदेश स्तर पर मिल सकेगा।

हरिचन्द्रपुर में आग से चार परिवार बेघर, विधायक रुदौली ने बांटी राहत सामग्री

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।विधानसभा क्षेत्र रुदौली अंतर्गत ग्राम पंचायत रेछ के हरिचन्द्रपुर गांव में लगी आग से चार परिवारों का आशियाना जलकर खाक हो गया।आग की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली।

अग्निकांड में घर में रखा बर्तन, कपड़ा, अनाज व अन्य दैनिक उपयोग

की सामग्री जलकर नष्ट हो गई। प्रभावित परिवारों में दुर्योधन रावत,अनन्त राम रावत,आशाराम रावत तथा गुरु देई शामिल हैं।विधायक ने मौके पर ही पीड़ितों को बर्तन, कपड़े, तिरपाल सहित खाद्य सामग्री वितरित की तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों को शासन की ओर से मिलने वाली हर संभव सहायता शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।विधायक ने कहा कि संकट की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्हें हर स्तर पर मदद दिलाई जाएगी। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया।

नवागत डीएम इंद्रजीत सिंह ने संभाला कार्यभार, अफसरों ने किया स्वागत'

ब्यूरो चीफ – आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर । नवागत डीएम इंद्रजीत सिंह ने सुल्तानपुर में कार्यभार संभाल लिया। जिला कोषागार में चार्ज लेकर निवर्तमान डीएम कुमार हर्ष से मुलाकात की। डीएम ने शासन की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने और नई योजनाओं का ड्राफ्ट भेजने को प्राथमिकता बताया। सीडीओ विनय कुमार सिंह, एडीएम गौरव शुक्ला समेत सभी अफसरों ने बुके देकर स्वागत किया। डीएम के आगमन पर कलेक्ट्रेट में पुलिस–प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा।

स्मार्ट मीटर,महिला आरक्षण पर सरकार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने घेरा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मंगलवार को फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई अहम मुद्दों को लेकर जोरदार हमला बोला।उन्होंने आरोप लगाया कि शादी–विवाह के इस व्यस्त सीजन में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है और ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 4000 से 5000 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है।स्मार्ट मीटर के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका दावा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 76 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनकी वजह से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां पहले 1000 रुपये बिल आता था,अब वह बढ़कर 1500 से 2000 रुपये तक पहुंच रहा है। सांसद ने सभी स्मार्ट मीटर हटाने और उपभोक्ताओं से वसूली गई अतिरिक्त धनराशि वापस करने की मांग की।महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और इसे "राजनीतिक गेम" करार दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही 2023 में पारित हो चुका है और सरकार अब अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से जनता का ध्यान हटा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पहले अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि मौर्य "हारे हुए नेता" हैं और पार्टी की कृपा से उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं।आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद ने दावा किया कि 2027 में सपा सरकार बनाएगी और भाजपा सत्ता से बाहर होगी। सपा के निवर्तमान प्रवक्ता लवलेश पांडेय ने बताया कि प्रेसवार्ता में पूर्व मंत्री पवन पांडे, निवर्तमान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप, छोटेलाल यादव,जय सिंह यादव, ओपी पासवान,सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे।

सीडीओ व डीआईओएस ने राजकीय पुस्तकालय मे आयोजित पुस्तक मेला का किया शुभारम्भ

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। मंगलवार को पाठ्यक्रम आधारित यूपी बोर्ड की शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु अधिकृत गुणवत्ता परक एवं अत्यधिक कम मूल्य की पुस्तकों के विषय में जागरूकता हेतु पुस्तक जागरूकता एवं सुलभ शिविर मंगलवार को राजकीय पुस्तकालय में आयोजित किया गया।जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने किया।इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन तिवारी व सह जिला विद्यालय निरीक्षक अवनीश कुमार पाण्डेय मौजूद रहे।पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे पुस्तक मेले निश्चित रूप से समय–समय पर लगाते रहना चाहिए। कम मूल्य पर मिलने वाली यह पुस्तके निश्चित रूप से गरीब बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन तिवारी ने प्रकाशक को निर्देश दिया कि वह जिले के सभी प्रधानाचार्यो से संपर्क करके इन पुस्तकों को विद्यालयों तक पहुंचाएं जिससे दूर दराज क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों तक भी ऐसी पुस्तकें पहुंच सके। क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसी पुस्तक ना पहुंचने के कारण वहां के छात्र–छात्राएं लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसलिए जिले की हर तहसील अस्तर तक ऐसे पुस्तक मेलों का आयोजन होना चाहिए। जिससे गरीब करके छात्र–छात्राओं को उत्कृष्ट तथा कब मूल्य पर मिलने वाली पुस्तके उपलब्ध हो सके। मेले में कम मूल्यों पर मिल रही पुस्तकों को जिले के जी जीआईसी इंटर कॉलेज, जीजीआईसी इंटर कॉलेज,कनौसा कान्वेंट इंटर कॉलेज और कन्या इंटर कॉलेज सहित सैकड़ो बच्चों शिक्षकों तथा जिले के प्रधानाचार्यो ने खरीदा।जिले के कई विद्यालयों के बच्चे पुस्तक मेले में इन पुस्तकों को पढ़ने वि देखने आए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री आलोक तिवारी, प्रधानाचार्य परिषद के जिला मंत्री देवव्रत सिंह, जिला उपाध्यक्ष डॉ शिव कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य ममता निषाद, पूर्व प्रधानाचार्य मनोज वर्मा, प्रधानाचार्य अखिलेश उपाध्याय, प्रधानाचार्य उदयभान तिवारी, महानगर अध्यक्ष अनूप पांडेय आदि उपस्थित रहे।

जाम से मुक्तिदिलाने के लिए पुलिस प्रशासन मंथन मे जुटी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। रामनगरी में दो दिन के ट्रायल के बाद अब जिला प्रशासन का मुख्य केन्द्र बिंदु रामपथ के सबसे भीड़ भाड़ वाले हिस्से श्रीराम अस्पताल से हनुमानगढ़ी तिराहे तक करीब 150 मीटर क्षेत्र को पूरी तरह जाम मुक्त बनाने पर है।इसके लिए प्रशासन ए और बी दो तरह के प्लान पर काम कर रहा है, ताकि भीड़ रहने और न रहने की स्थिति में अलग–अलग व्यवस्था लागू की जा सके।जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालु अपने वाहनों से अधिकतम दूरी तक राम मंदिर के करीब पहुंच सकें,जिससे उन्हें पैदल कम चलना पड़े। साथ ही स्थानीय निवासियों को आवागमन में होने वाली दिक्कतों से राहत देने के लिए भी विशेष रणनीति बनाई जा रही है।देखा जाये तो दो दिन के ट्रायल के दौरान रामपथ और संपर्क मार्गों के 52 बैरियर से वाहनों की रोक हटा दी गई थी।इस दौरान मालवाहन से लेकर चार पहिया वाहन तक सभी मार्गों पर सुचारु रूप से चलते नजर आए।हालांकि, टेढ़ी बाजार से लता मंगेशकर चौराहे के बीच केवल श्रीराम अस्पताल से हनुमानगढ़ी तिराहे तक ही वाहनों का दबाव ज्यादा दिखा।बाकी मार्गों पर जाम की स्थिति नहीं रही।ट्रायल के दौरान यह भी सामने आया कि कई संवेदनशील बैरियरों पर बिना जांच के ही वाहनों को प्रवेश मिलता रहा। कई जगह पुलिसकर्मी केवल डायवर्जन तक सीमित नजर आए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर से लगभग तीन किलोमीटर के दायरे में कई नई पार्किंग बनाने की योजना है। पुराने धर्मकांटा चौराहे के पास पार्किंग बनने के बाद बाहरी वाहनों को वहीं तक आने की अनुमति दी जा सकती है।

अयोध्या कैंट की ओर से आने वाले वाहनों को सामान्य दिनों में टेढ़ी बाजार और श्रीराम अस्पताल बैरियर तक आने की छूट देने पर भी सहमति बनी है। देखा जाए तो रामनगरी में इस समय सबसे अधिक चुनौती ई–रिक्शा और गोल्फ कार्ट है।श्रीराम अस्पताल बैरियर के पास इनकी लंबी कतारें नजर आईं। वहीं,हनुमानगढ़ी तिराहे तक ठेले–खोमचे भी लाइन में लगे रहे, जिससे रास्ता संकरा हो गया। इस संबंध में सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि ई–रिक्शा को पूर्व की भांति राम पथ पर प्रतिबंधित रहेगा।सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि राम नगरी वासियों को आवागमन में कोई परेशानी न हो,इसके लिए काम किया जा रहा है।शहर के 52 स्थानों पर बैरियर को अयोध्या वासियों और श्रद्धालुओं को खोल दिया गया है।कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति बन रही है, जिसके लिए प्लान के अनुसार काम किया जा रहा है, बैरियर फिलहाल यथावत बने रहेंगे,लेकिन अब वहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्री वाहनों के आवागमन को भी नियंत्रित रूप से अनुमति दी जाएगी।अधिकारियों के अनुसार, पहले भी जरूरत के आधार पर बैरियरों पर वाहनों के प्रवेश को सीमित किया जाता था।अब नई समीक्षा बैठक के बाद यातायात व्यवस्था में और लचीलापन लाते हुए वाहनों के आवागमन की छूट कुछ और बढ़ाई जाएगी, ताकि सुरक्षा और सुविधा दोनों का संतुलन बना रहे।वही यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने कई सुझाव दिए हैं।गोल्फ कार्ट और ई–रिक्शा की संख्या सीमित की जाए, इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाई जाएं।फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कर पैदल आवागमन बढ़ाया जाए।श्रीराम अस्पताल से कोतवाली तक ई–रिक्शा पूरी तरह प्रतिबंधित हों।

'परिवहन मंत्री ने किया नवनिर्मित रोडवेज बस स्टैंड का लोकार्पण'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' सोमवार को पाली नगर के बैरियर चौराहे पर नवनिर्मित रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटनध्लोकार्पण परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फीता काटकर किया साथ ही उन्होंने रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर नई सेवा का शुभारंभ किया।लोकार्पण समारोह में सवायजपुर क्षेत्र विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंहश्रानूश विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रोडवेज बस स्टैंड बनने से अब यात्रियों के लिए पाली से बड़े नगरों के साथ –साथ कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिये बस सेवा सुगम होगी। अब पाली क्षेत्रवासियों को लंबी दूरी तय करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के अथक प्रयासों से लंबे समय से इंतजार कर रहे पाली क्षेत्रवासियों का सपना साकार हुआ है। बस स्टैंड के लोकार्पण से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोकार्पण के दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि रोडवेज बस

स्टैंड के शुरू होने से पाली क्षेत्र के लोगों को बेहतर,सुरक्षितऔर सुविधाजनक

परिवहन की सेवा उपलब्ध होने के साथ ही क्षेत्र का विकास होगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पाली में रोडवेज बस स्टैंड बन जाने से आमजन को आवागमन में आसानी होगी और साथ ही पाली क्षेत्र के लिए बस स्टैंड एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर हरदोई क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश कुमार,ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह श्सेनानीश, गन्ना समिति के चेयरमैन ओम प्रकाश मिश्रा,उपजिलाधिकारी अंकित तिवारी,विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी,मंडल अध्यक्ष राकेश रंजन त्रिवेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवम तिवारी,जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह,अनंगपुर मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह,भाजपा नेता कुलदीप मिश्रा सहित कई भाजपा नेता ,सभासद, प्रधान और स्थानीय गणमान्य नागरिक काफी संख्या में मौजूद रहे।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं ने जताया आक्रोश

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले के तहसील बीकापुर क्षेत्र के प्रीपेड स्मार्ट मीटरो में हो रही गड़बड़ियों और ज्यादा आ रहे बिलों को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश पनप रहा है।मंगलवार को दर्जनों उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने उप जिलाधिकारी से मिलकर इसे हटवाने की मांग की । साथ में दस दिनों के अन्दर न हटाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।तहसील क्षेत्र बीकापुर के विद्युत उपकेंद्र केरालाल खा अंतर्गत ग्राम पंचायत जाना चौबेपुर स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं मे सूबेदार, राजकुमार, विपता, बासमती, सहित दर्जनों लोगों ने बीकापुर तहसील पहुंचकर विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए इस मीटर को हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी श्रेया को दिया। वही संयुक्त मोर्चा के संयोजक मायाराम वर्मा ,शेख मोहम्मद इशहाकध,मायाराम यादव ,जनौस के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर बहादुर शेर, बार ऐसोशियन के पूर्व अध्यक्ष मोइनुद्दीन, विश्वास राणा, रमेश सहित दर्जनो लोगों ने हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र देकर दस दिनो के अंदर उपभोक्ताओं के घर लगे प्रीपेड मीटर को हटवाने की मांग की । साथ में न हटाने की दशा में विद्युत विभाग के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

मिशन शक्ति फेस 2 के तहत प्रशिक्षु आईपीएस शुभम जैन व महिला पुलिस कर्मियों ने किया महिलाओ को जागरूक

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। थाना पूराकलंदर में प्रशिक्षु आईपीएस शुभम् जैन की अगुवाई में मंगलवार को पूराकलंदर थाना क्षेत्र के माधव सर्वोदय स्कूल में छात्राओं को जागरूक किया गया वही महिला अपराध से संबंधित दिशा निर्देश एवं जरूरी जानकारी दी गई।आईपीएस शुभम् जैन ने छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया किसी भी अपराध होने होने की आशंका पर तत्काल शासन द्वारा जनता के लिए जारी किए नम्बर 100,102 ,112,1076, 108,1090,181 पर सूचना देकर मदद ले सकते है वही छात्राओं को शासन और पुलिस की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।वही महिला दरोगा खुशबू यादव एवं पूर्णिमा सिंह ने छात्राओं को जागरूक किया वही सुनसान जगहों पर न जाने की सलाह दी छात्राओं को दुराचारियों से बचने की सलाह और कार्यवाही के लिए सूचना नंबरों की जानकारी दी।कार्यक्रम के अंत में आईपीएस शुभम् जैन ने छात्राओं को डिजिटल माध्यमों से भी छात्राओं को उनके अधिकार सुरक्षा के बारे में जानकारी दी।कार्यक्रम में महिला सिपाही दीक्षा मिश्रा दरोगा आकाश यादव सिपाही सुशील कुमार राजकुमार यादव समेत कई पुलिस कर्मी मौजूद रहे और छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया तो हर समय पुलिस मदद का भरोसा दिलाया।

किसान की मौत से नाराज ग्रामीणों ने जिटकरी,बौखर मार्ग किया जाम

उन्नाव, (संवाददाता)। जिटकरी गांव में शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे डंपर से कुचलकर किसान की मौत के 33 घंटे बाद भी न तो आरोपी वाहन का पता चल सका और न ही प्राथमिकी दर्ज हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने रविवार को जिटकरी–बौखर मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ जाम शाम साढ़े चार बजे प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। इस दौरान सड़क पर सैकड़ों ओवरलोड डंपर खड़े रहे। जिटकरी गांव में शनिवार सुबह पैदल खेतों की ओर जा रहे किसान फूल सिंह को बेकाबू डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भाग गया था जबकि घायल किसान करीब डेढ़ घंटे तक खनन–मार्ग में तड़पता रहा। परिजन एक किराये के साधन से घायल किसान को अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रशासन की कोई कार्रवाई न होने पर रविवार को ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीण शैलेंद्र प्रताप, उदयराज आदि ने बताया कि हादसा करने वाले डंपर और चालक पर कार्रवाई, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। जर्जर सड़क की मरम्मत कराई जाए। आरोप है कि प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कराने की बात तो कही लेकिन मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर पहुंचे जरिया थाना प्रभारी दिनेश पांडेय, क्षेत्राधिकारी साहरुख खान और तहसीलदार रविंद्र पाल ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। जिटकरी के ग्रामीणों की आंखों में गुस्से के साथ बेबसी भी साफ झलक रही है। शैलेंद्र, उदयराज राजपूत, प्रताप राजपूत, हरिसिंह राजपूत, बहादुर, धूराम वर्मा, छुन्ना, प्रकाश, निशांत, अर्जुन, मोतीलाल, जगपाल, सुगर माथव और पुट्टी राजपूत का आरोप है कि न्याय की मांग लेकर थाने पहुंचे थे लेकिन उन्हें आश्वासन और प्रक्रिया में उलझा दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सोमवार को आने व दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है अगर हादसे के बाद भी सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा तो फिर किसी और घर का चिराग बुझने में देर नहीं लगेगी। ग्रामीणों का कहना है कि जिटकरी बौखर मार्ग पर रोजाना तेज रफ्तार से डंपर दौड़ते हैं। कच्ची और जर्जर सड़क, उड़ती धूल और पानी के छिड़काव के अभाव में हालात और खतरनाक हो जाते हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।